

BiharBoardBooks.Com

Bihar Board Textbooks, Notes & Question Papers

Bihar Board 12th 322- POLITICAL SCIENCE Solved Paper

खण्ड अ / Section-A: वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

Q1. संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे?

- (A) जवाहर लाल नेहरू
- (B) सरदार पटेल
- (C) डॉ राजेन्द्र प्रसाद
- (D) डॉ बी०आर० अम्बेडकर

Q2. संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई?

- (A) 9 दिसम्बर 1946
- (B) 15 अगस्त 1947
- (C) 26 जनवरी 1948
- (D) 14 अगस्त 1946

Q3. संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे?

- (A) 384
- (B) 388
- (C) 389

- (D) 392

Q4. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?

- (A) डॉ० बी०आर० अम्बेडकर
- (B) सरदार पटेल
- (C) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
- (D) सी० राजगोपालाचारी

Q5. किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया?

- (A) हिन्दू महासभा
- (B) समाजवादी पार्टी
- (C) मुस्लिम लीग
- (D) इनमें से कोई नहीं

Q6. प्रारम्भ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे?

- (A) 395
- (B) 375
- (C) 385
- (D) 350

Q7. वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं?

- (A) 25
- (B) 24
- (C) 23
- (D) 22

Q8. भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है?

- (A) 40
- (B) 42
- (C) 43
- (D) 44

Q9. भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

Q10. किसने कहा कि 'भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है'?

- (A) प्रो० आइबर जेनिंग्स
- (B) के० वी० राव
- (C) सरदार पटेल
- (D) जवाहर लाल नेहरू

Q11. स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?

- (A) सी० राजगोपालाचारी
- (B) लार्ड माउण्टबेटन
- (C) कामराज
- (D) डॉ राजेन्द्र प्रसाद

Q12. भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है?

- (A) संसद
- (B) प्रधानमंत्री
- (C) जनता
- (D) राष्ट्रपति

Q13. संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी?

- (A) दिल्ली
- (B) मद्रास
- (C) कलकत्ता
- (D) बम्बई

Q14. भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था?

- (A) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
- (B) के० एम० मुंशी
- (C) डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा
- (D) सी० राजगोपालाचारी

Q15. किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है?

- (A) समानता का अधिकार
- (B) स्वतंत्रता का अधिकार
- (C) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- (D) सवैधानिक उपचारों का अधिकार

Q16. वर्तमान मे भारतीय संविधान मे कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है?

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 11
- (D) 12

Q17. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है?

- (A) 18
- (B) 15
- (C) 16
- (D) 17

Q18. अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है?

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7

Q19. किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है?

- (A) धर्म का
- (B) शिक्षा का
- (C) सम्पत्ति का
- (D) समता का

Q20. कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद मे दिया गया है?

- (A) 14
- (B) 15
- (C) 16
- (D) 17

Q21. सम्पत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है?

- (A) विधिक अधिकार
- (B) मानव अधिकार
- (C) मूल अधिकार
- (D) नैसर्गिक अधिकार

Q22. राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं?

- (A) भाग-2
- (B) भाग-3
- (C) भाग-4
- (D) भाग-5

Q23. मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन 'रिट' जारी कर सकते हैं?

- (A) सर्वोच्च न्यायालय
- (B) संसद
- (C) राष्ट्रपति
- (D) मुख्य चुनाव आयोग

Q24. मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है?

- (A) राष्ट्रपति
- (B) सर्वोच्च न्यायालय

- (C) संसद
- (D) प्रधानमंत्री

Q25. किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है?

- (A) 24वाँ
- (B) 25वाँ
- (C) 42वाँ
- (D) 73वाँ

Q26. संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है?

- (A) 320
- (B) 368
- (C) 370
- (D) 390

Q27. अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है?

- (A) चुनाव आयोग
- (B) वित्त आयोग
- (C) उच्च न्यायालय
- (D) इनमें से कोई नहीं

Q28. मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

Q29. राज्य के प्रमुख कौन हे?

- (A) प्रधानमंत्री
- (B) राष्ट्रपति
- (C) उपराष्ट्रपति
- (D) कोई नहीं

Q30. किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों मे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है?

- (A) 350
- (B) 352
- (C) 356
- (D) 360

Q31. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है?

- (A) राष्ट्रपति
- (B) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश
- (C) मुख्य चुनाव आयुक्त
- (D) प्रधानमंत्री

Q32. मंत्री परिषद् सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?

- (A) लोकसभा
- (B) राज्यसभा
- (C) प्रधानमंत्री
- (D) राष्ट्रपति

Q33. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे?

- (A) लोकसभा
- (B) राज्यसभा
- (C) विधान परिषद्
- (D) कोई नहीं

Q34. निम्न में कौन राज्य में केन्द्र का प्रतिनिधि होता है?

- (A) मुख्यमंत्री
- (B) राज्यपाल
- (C) उच्च न्यायालय
- (D) इनमें से कोई नहीं

Q35. भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हैं?

- (A) द्रौपदी मूर्मू
- (B) मीरा कुमार
- (C) प्रतिभा पाटिल
- (D) सरोजिनी नाइडू

Q36. किस राज्य के विधान मण्डल में विधान परिषद् नहीं है?

- (A) बिहार
- (B) उत्तर प्रदेश
- (C) तमिलनाडु
- (D) महाराष्ट्र

Q37. किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं?

- (A) 500

- (B) 400
- (C) 300
- (D) 200

Q38. संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

- (A) प्रधानमंत्री
- (B) राष्ट्रपति
- (C) उपराष्ट्रपति
- (D) लोकसभा का अध्यक्ष

Q39. निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है?

- (A) लोकसभा
- (B) राज्यसभा
- (C) लोकसभा एवं राज्य सभा
- (D) इनमें से कोई नहीं

Q40. 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थीं?

- (A) 98
- (B) 99
- (C) 100
- (D) 101

Q41. धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है?

- (A) वित्त मंत्री

- (B) प्रधानमंत्री
- (C) राष्ट्रपति
- (D) गृहमंत्री

Q42. लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है?

- (A) प्रधानमंत्री
- (B) लोकसभा अध्यक्ष
- (C) राष्ट्रपति
- (D) उपराष्ट्रपति

Q43. कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है?

- (A) राष्ट्रपति
- (B) प्रधानमंत्री
- (C) उपपराष्ट्रपति
- (D) कानून मंत्री

Q44. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

- (A) 4 वर्ष
- (B) 5 वर्ष
- (C) 6 वर्ष
- (D) 8 वर्ष

Q45. लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं?

- (A) 20
- (B) 21
- (C) 22

- (D) 23

Q46. लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है?

- (A) सुमित्रा महाजन
- (B) मीरा कुमार
- (C) प्रतिभा पाटिल
- (D) सरोजनी नायडू

Q47. भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है?

- (A) वकील
- (B) पक्षकार
- (C) महान्यायवादी
- (D) इनमें से कोई नहीं

Q48. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु कितनी है?

- (A) 60 वर्ष
- (B) 62 वर्ष
- (C) 65 वर्ष
- (D) 70 वर्ष

Q49. भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है?

- (A) कलकत्ता उच्च न्यायालय
- (B) मद्रास उच्च न्यायालय
- (C) मुम्बई उच्च न्यायालय
- (D) इनमें से कोई नहीं

Q50. भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गयी है?

- (A) अमेरिका
- (B) ब्रिटेन
- (C) फ्रांस
- (D) कनाडा

Q51. किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय 'रीट' जारी कर सकता है?

- (A) 220
- (B) 224
- (C) 226
- (D) 228

Q52. भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं?

- (A) केन्द्र सरकार
- (B) संसद
- (C) सर्वोच्च न्यायालय
- (D) राज्य

Q53. संघ सूची में कुल कितने विषय हैं?

- (A) 97
- (B) 66
- (C) 47
- (D) 100

Q54. संविधान के किस अनुसूची में केन्द्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है?

- (A) पाँचवी

- (B) छठी
- (C) सातवी
- (D) आठवीं

Q55. भारतीय संविधान अर्द्ध-संघात्मक है, किसने कहा?

- (A) एम० वी० पायली
- (B) आइवर जोनिंग्स
- (C) के० सी० व्हीयर
- (D) कोई नहीं

Q56. विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है?

- (A) संघ सूची
- (B) राज्य सूची
- (C) समवर्ती सूची
- (D) कोई नहीं

Q57. संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है?

- (A) 24वाँ
- (B) 42वाँ
- (C) 45वाँ
- (D) 73वाँ

Q58. भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई?

- (A) राजस्थान
- (B) बिहार
- (C) उत्तर प्रदेश

- (D) मध्य प्रदेश

Q59. पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?

- (A) 15 अगस्त
- (B) 26 जनवरी
- (C) 24 अप्रैल
- (D) 14 नवम्बर

Q60. 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?

- (A) 10वीं
- (B) 11वीं
- (C) 12वीं
- (D) 13वीं

Q61. भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है?

- (A) कनाडा
- (B) आस्ट्रेलिया
- (C) ब्रिटेन
- (D) दक्षिण अफ्रीका

Q62. संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है?

- (A) 352
- (B) 356
- (C) 360
- (D) 362

Q63. किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा?

- (A) ग्रेनविल आस्टिन
- (B) एच०वी० कामथ
- (C) के०टी० शाह
- (D) हॉबहाऊस

Q64. दल-बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया?

- (A) 50वाँ
- (B) 51वाँ
- (C) 52वाँ
- (D) 53वाँ

Q65. भारत में प्रथम लोक सभा का चुनाव कब हुआ?

- (A) 1950
- (B) 1951
- (C) 1952
- (D) 1953

Q66. संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह माँग सकते हैं?

- (A) 141
- (B) 142
- (C) 143
- (D) 144

Q67. संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गयी है?

- (A) 15वाँ

- (B) 16वाँ
- (C) 17वाँ
- (D) 18वाँ

Q68. सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला 'संविधान के मूल संरचना' सिद्धांत से जुड़ा हुआ है?

- (A) गोलक नाथ केस
- (B) केशवानन्द केस
- (C) मेनका गाँधी केस
- (D) इनमें से कोई नहीं

Q69. भारतीय संविधान को कब लागू किया गया?

- (A) 15 अगस्त 1947
- (B) 26 जनवरी 1949
- (C) 26 जनवरी 1950
- (D) इनमें से कोई नहीं

Q70. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधान सभा को भंग कर सकते हैं?

- (A) 170
- (B) 172
- (C) 174
- (D) 176

Q71. भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं?

- (A) 9

- (B) 11
- (C) 12
- (D) 14

Q72. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है?

- (A) यू०एस०ए०
- (B) कनाडा
- (C) आस्ट्रेलिया
- (D) आयरलैंड

Q73. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया?

- (A) बेरुबरी केस
- (B) मेनका गाँधी केस
- (C) गोलकनाथ केस
- (D) केशवानन्द भारती केस

Q74. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है?

- (A) लिखित संविधान
- (B) संसदीय सरकार
- (C) संघात्मक सरकार
- (D) एकात्मक सरकार

Q75. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान नहीं है?

- (A) संविधान की सर्वोच्चता

- (B) शक्ति का विभाजन
- (C) निष्पक्ष न्यायपालिका
- (D) दोहरी नागरिकता

Q76. राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है?

- (A) मुख्य न्यायाधीश
- (B) संसद
- (C) उप राष्ट्रपति
- (D) प्रधानमंत्री

Q77. 'मूल संरचना' का सिद्धांत किस केस से संबंधित है?

- (A) केशवानन्द भारती केस
- (B) गोलकनाथ केस
- (C) मिनर्वा केस
- (D) कोई नहीं

Q78. धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है?

- (A) 20-25
- (B) 25-28
- (C) 28-30
- (D) 30-31

Q79. चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3

- (D) 4

Q80. राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं?

- (A) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (B) मुख्य चुनाव आयुक्त
- (C) प्रधानमंत्री
- (D) गृहमंत्री

Q81. यू०पी०एस०सी० के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है?

- (A) 315
- (B) 317
- (C) 320
- (D) 322

Q82. संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है?

- (A) 352
- (B) 356
- (C) 358
- (D) 360

Q83. राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है?

- (A) 25 वर्ष
- (B) 30 वर्ष
- (C) 35 वर्ष
- (D) 40 वर्ष

Q84. सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया?

- (A) राजेन्द्र प्रसाद
- (B) राधाकृष्णन
- (C) बूटा सिंह
- (D) ज्ञानी जैल सिंह

Q85. संविधान के तीसरे भाग में दिये गये मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है?

- (A) स्वतंत्रता का
- (B) समानता का
- (C) धर्म का
- (D) इनमें से कोई नहीं

Q86. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?

- (A) राजीव कुमार
- (B) ज्ञानेश कुमार
- (C) विवेक जोशी
- (D) सुखवीर सिन्धू

Q87. वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है?

- (A) 3 वर्ष
- (B) 4 वर्ष
- (C) 5 वर्ष
- (D) 6 वर्ष

Q88. राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है?

- (A) सर्वोच्च न्यायालय
- (B) संसद
- (C) प्रधानमंत्री
- (D) राज्य के विधान मंडल

Q89. राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

Q90. नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?

- (A) राष्ट्रपति
- (B) प्रधानमंत्री
- (C) वित्त मंत्री
- (D) गृह मंत्री

Q91. विधान परिषद् के सदस्यों की अवधि क्या होती है?

- (A) 2 वर्ष
- (B) 4 वर्ष
- (C) 5 वर्ष
- (D) 6 वर्ष

Q92. कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किस अधिकतम अवधि के लिए?

- (A) 9 माह

- (B) 3 माह
- (C) 12 माह
- (D) 6 माह

Q93. सरकार के कितने अंग होते हैं?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

Q94. किस राज्य से पृथक होकर सन् 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया?

- (A) उत्तर प्रदेश
- (B) आन्ध्र प्रदेश
- (C) मध्य प्रदेश
- (D) कर्नाटक

Q95. भारत में क्षेत्रिय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है?

- (A) केन्द्रीय गृह मंत्री
- (B) प्रधानमंत्री
- (C) राष्ट्रपति
- (D) राज्यपाल

Q96. राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है?

- (A) राज्यपाल
- (B) केन्द्रीय गृह मंत्री
- (C) राष्ट्रपति

- (D) प्रधानमंत्री

Q97. वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

Q98. भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ?

- (A) 1950
- (B) 1951
- (C) 1952
- (D) 1953

Q99. भारत कैसा गणराज्य है?

- (A) धर्मनिरपेक्ष
- (B) संप्रमुख
- (C) समाजवादी
- (D) सभी कथन सही हैं

Q100. भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं?

- (A) 17
- (B) 18
- (C) 19
- (D) 20

खण्ड ब / Section-B: लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है?

भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। यह संविधान के मूल आदर्शों, उद्देश्यों और दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को स्थापित करने का संकल्प लेती है। न्यायालयों के लिए यह संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है और सरकार के स्वरूप (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य) को स्पष्ट करती है।

2. भारतीय संविधान की दो मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं:

1. **लिखित और विस्तृत संविधान:** यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं।
2. **संसदीय शासन प्रणाली:** इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) सामूहिक रूप से विधायिका (लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होती है।

3. भारत की संविधान सभा पर एक टिप्पणी लिखें?

भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसका मुख्य कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष और डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कुल 389 सदस्य (प्रारंभ में) थे। 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन के परिश्रम के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया।

4. भारतीय संविधान के कोई चार एकात्मक लक्षण बताएँ?

भारतीय संविधान के चार एकात्मक लक्षण निम्नलिखित हैं:

1. **एकल नागरिकता:** पूरे देश के लिए केवल एक ही नागरिकता है।
2. **सशक्त केंद्र:** केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।
3. **एकीकृत न्यायपालिका:** सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और पूरे देश के लिए एक ही न्यायिक व्यवस्था है।
4. **राज्यपाल की नियुक्ति:** राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति (केंद्र) द्वारा होती है, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

5. भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की प्रकृति क्या है?

भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) न तो पूरी तरह लचीली है और न ही पूरी तरह कठोर। यह दोनों का मिश्रण है। कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, कुछ के लिए विशेष बहुमत (2/3) की आवश्यकता होती है, और कुछ संघीय प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है।

6. मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं?

मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) के लिए आवश्यक हैं। ये अधिकार संविधान के भाग-3 (अनुच्छेद 12-35) में दिए गए हैं और न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय हैं। यदि इनका उल्लंघन होता है, तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं।

7. मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है?

मौलिक अधिकार वाद-योग्य (justiciable) हैं, अर्थात् इनके उल्लंघन पर न्यायालय जाया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद-योग्य नहीं हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक (राज्य को रोकने वाले) होते हैं, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक (राज्य को कुछ करने का निर्देश देने वाले) होते हैं।

8. नागरिकों के दो धार्मिक अधिकारों का वर्णन करे?

नागरिकों के दो धार्मिक अधिकार (अनुच्छेद 25-28 के तहत) हैं:

1. **अंतःकरण की स्वतंत्रता:** किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।
2. **धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता:** प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने और चल-अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है।

9. शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है?

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) कमजोर वर्गों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार (human trafficking) और बेगार (बिना वेतन के काम) पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है।

10. भारतीय चुनाव आयोग के दो कार्यों का वर्णन करे?

भारतीय चुनाव आयोग के दो प्रमुख कार्य हैं:

1. **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना:** संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करना।
2. **मतदाता सूची तैयार करना:** चुनाव से पहले पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करना और समय-समय पर उसे अद्यतन (update) करना।

11. राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है?

राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (pleasure of the President) अपने पद पर बना रहता है। सामान्यतः, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो उस राज्य का निवासी न हो।

12. मंत्री परिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं?

सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि पूरी मंत्रिपरिषद् एक इकाई के रूप में कार्य

करती है और लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। सभी मंत्री एक-दूसरे के निर्णयों का समर्थन करते हैं।

13. राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करें?

संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61) चलाया जा सकता है। इसका प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आरोप लगाने वाले सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। यदि वह सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है।

14. संसदीय शासन की दो विशेषताएँ बताएँ?

1. **दोहरी कार्यपालिका:** इसमें नाममात्र का प्रमुख (राष्ट्रपति) और वास्तविक प्रमुख (प्रधानमंत्री) अलग-अलग होते हैं।
2. **कार्यपालिका और विधायिका का समन्वय:** मंत्री विधायिका के सदस्य होते हैं और उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं।

15. मुख्यमंत्री के किन्हीं दो कार्यों की विवेचना करें?

1. **मंत्रिपरिषद का गठन:** मुख्यमंत्री अपनी टीम के मंत्रियों का चयन करता है और राज्यपाल को उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है।
2. **नीति निर्माण और प्रशासन:** वह राज्य सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है और विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।

16. राज्यसभा के दो विशेष अधिकारों को लिखें?

1. **राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार:** अनुच्छेद 249 के तहत, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।
2. **नई अखिल भारतीय सेवाएँ:** अनुच्छेद 312 के तहत, वह नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

17. लोकसभा की कार्यपालिक शक्ति क्या है?

लोकसभा की कार्यपालिक शक्ति यह है कि वह कार्यपालिका (सरकार) पर नियंत्रण रखती है। वह प्रश्नकाल, शून्यकाल, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रियों को जवाबदेह बनाती है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।

18. सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति क्या है?

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे शून्य या अवैध घोषित कर सकता है।

19. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है?

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिए कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) का पालन किया जाता है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह नामों की सिफारिश करता है। इन सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।

20. 73वाँ एवं 74वाँ संविधान के महत्व पर प्रकाश डालें?

73वें और 74वें संशोधन (1992) ने भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'पंचायती राज व्यवस्था' और 74वें संशोधन ने शहरी क्षेत्रों के लिए 'नगरपालिका' की स्थापना की। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ।

21. नक्सलवाद क्या है?

नक्सलवाद एक उग्र वामपंथी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई थी। यह माओवादी विचारधारा से प्रेरित है और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से मौजूदा राजनीतिक सत्ता को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता है। यह मुख्य रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में भूमि सुधार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का दावा करता है।

22. भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका स्पष्ट करें?

भारतीय राजनीति में जाति एक प्रभावशाली कारक है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हैं। मतदाता भी अक्सर अपनी जाति के उम्मीदवार या दल को वोट देते हैं। जाति आधारित दबाव समूह और पार्टियाँ (जैसे बसपा, सपा आदि) नीति निर्माण और सत्ता के बंटवारे को प्रभावित करती हैं।

23. सम्प्रदायिकतावाद की समस्या के दो कारण बताएँ?

1. **वोट बैंक की राजनीति:** राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं।

2. **ऐतिहासिक और सामाजिक पूर्वाग्रह:** अतीत के कड़वे अनुभव और एक-दूसरे के धर्म के प्रति गलतफहमियाँ या असहिष्णुता सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं।

24. क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं?

क्षेत्रीयता वह भावना है जिसमें लोग अपने क्षेत्र, भाषा या संस्कृति के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं और उसे राष्ट्रहित से ऊपर मानते हैं। यह भावना कभी-कभी अलग राज्य की मांग या स्वायत्तता के संघर्ष का रूप ले लेती है। यह "धरती पुत्र" (Sons of the Soil) के सिद्धांत को भी जन्म देती है।

25. नेम की (NAM) दो उपलब्धियाँ लिखें?

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की दो उपलब्धियाँ:

1. **शीत युद्ध के तनाव को कम करना:** इसने दो महाशक्तियों (अमेरिका और सोवियत संघ) के बीच तनाव कम करने और विश्व शांति बनाए रखने में मदद की।

2. **नव-स्वतंत्र देशों की संप्रभुता की रक्षा:** इसने नए आजाद हुए देशों को किसी भी गुट में शामिल होने के दबाव से बचाया और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का मंच दिया।

26. शीत युद्ध क्या है?

शीत युद्ध (1945-1991) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका (USA) और सोवियत संघ (USSR) के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव की स्थिति थी। इसमें

प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दोनों गुटों के बीच हथियारों की होड़, जासूसी और छद्म युद्ध (Proxy Wars) जारी रहे। यह पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का संघर्ष था।

27. भारतीय विदेश नीति की दो विशेषताएँ लिखें?

1. **गुटनिरपेक्षता:** भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और हर मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेता है।
2. **पंचशील और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व:** भारत दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, अनाक्रमण और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने (पंचशील सिद्धांत) में विश्वास रखता है।

28. सार्क का क्या महत्व है?

सार्क (SAARC - दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का मंच है। इसका महत्व क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने में है। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार, आतंकवाद और गरीबी जैसी साझा समस्याओं को सुलझाने के लिए बातचीत का अवसर प्रदान करता है।

29. ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्य बताएँ?

1. **नागरिक सुविधाएँ:** गाँव में स्वच्छता, पेयजल, सड़कों का रखरखाव और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2. **विकास कार्य:** कृषि, पशुपालन और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना तथा मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं को लागू करना।

30. आसियान क्या है?

आसियान (ASEAN - दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन) दक्षिण-पूर्व एशिया के 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

31. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिन्दुओं की व्याख्या करें?

भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की 'कुंजी' और 'आत्मा' कहा जाता है। यह संविधान के दर्शन को स्पष्ट करती है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. **स्रोत:** प्रस्तावना की शुरुआत "हम भारत के लोग" से होती है, जो यह दर्शाता है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है।
2. **राज्य का स्वरूप:** यह भारत को एक 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' घोषित करती है। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, समाज में समानता का लक्ष्य रखता है, किसी धर्म विशेष को राजधर्म नहीं मानता और शासक जनता द्वारा चुना जाता है।
3. **न्याय:** यह नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक—प्रदान करने का वादा करती है।
4. **स्वतंत्रता और समानता:** इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
5. **बंधुत्व:** यह व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प लेती है। इस प्रकार, प्रस्तावना संविधान के उच्च आदर्शों का सारांश है।

32. संविधान के भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करें?

भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। वर्तमान में नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्राप्त हैं:

1. **समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18):** कानून के समक्ष समानता, धर्म-जाति-लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, लोक नियोजन में अवसर की समानता और अस्पृश्यता व उपाधियों का अंत।

2. **स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22):** इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, घूमने और निवास की स्वतंत्रता शामिल है। साथ ही अपराधों के लिए दोषसिद्धि और जीवन की सुरक्षा का अधिकार भी है।
3. **शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24):** मानव दुर्व्यापार, बेगार और बाल श्रम पर प्रतिबंध।
4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28):** किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी।
5. **संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30):** अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने तथा शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार।
6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32):** मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। इसे डॉ. अंबेडकर ने संविधान की 'आत्मा' कहा है।

33. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व का वर्णन करे?

संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) वे निर्देश हैं जो राज्य को कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। इनका महत्व निम्नलिखित है:

1. **कल्याणकारी राज्य की स्थापना:** इनका मुख्य उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करे।
2. **सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र:** जहाँ मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
3. **सरकार के लिए मार्गदर्शक:** ये सरकार के लिए एक 'प्रकाश स्तंभ' की तरह हैं, जो उसे शासन संचालन में दिशा दिखाते हैं।

4. **शासन के मूल्यांकन का आधार:** जनता इनके आधार पर सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर सकती है कि सरकार ने जनकल्याण के लिए कितना काम किया।
5. **संविधान की व्याख्या में सहायक:** न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करते समय इन तत्वों का सहारा लेती है। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी शासन में इन्हें मूलभूत माना गया है।

34. भारत के निर्वाचन आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें?

भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। इसका मुख्य कार्य देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है।

- **संरचना:** वर्तमान में यह एक बहु-सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **कार्य:** इसके प्रमुख कार्यों में संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना शामिल है। यह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता भी लागू करता है।
- **स्वतंत्रता:** आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार, भारतीय लोकतंत्र की सफलता में निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

35. भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या करें?

भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है।

- **भूमिका और शक्तियाँ:** प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है; वह मंत्रियों का चयन करता है और उनके विभागों का बंटवारा करता है। वह नीति आयोग

का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। वह सरकार की प्रमुख नीतियों की घोषणा करता है और संसद में सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल और विदेश नीति में भी उसकी निर्णायक भूमिका होती है।

- **आलोचनात्मक पक्ष:** हाल के दशकों में प्रधानमंत्री की भूमिका 'प्रधान' से बढ़कर 'राष्ट्रपतिनुमा' होती जा रही है। गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की शक्ति कभी-कभी सहयोगी दलों के दबाव में कमजोर पड़ जाती है। दूसरी ओर, पूर्ण बहुमत वाली सरकार में प्रधानमंत्री का अत्यधिक वर्चस्व कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी को कमजोर कर सकता है। आलोचकों का मानना है कि शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। निष्कर्षतः, प्रधानमंत्री 'समकक्षों में प्रथम' से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उस पर संसद और संविधान का नियंत्रण भी आवश्यक है।

36. लोकसभा के कार्य और शक्ति की विवेचना करें?

लोकसभा भारतीय संसद का लोकप्रिय और निम्न सदन है, जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी प्रमुख शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं:

1. **विधायी शक्तियाँ:** लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लेकिन गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल के कारण उसकी ही जीत होती है।
2. **वित्तीय शक्तियाँ:** वित्तीय मामलों में लोकसभा सर्वोच्च है। धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। बजट भी लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है।
3. **कार्यपालिका पर नियंत्रण:** मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को हटा सकती है।

4. **संविधान संशोधन:** वह राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है।
5. **निर्वाचन संबंधी कार्य:** वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। इस प्रकार, लोकतंत्र में जनता की प्रतिनिधि संस्था होने के कारण लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है।

37. सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं अधिकार क्षेत्र की विवेचना करें?

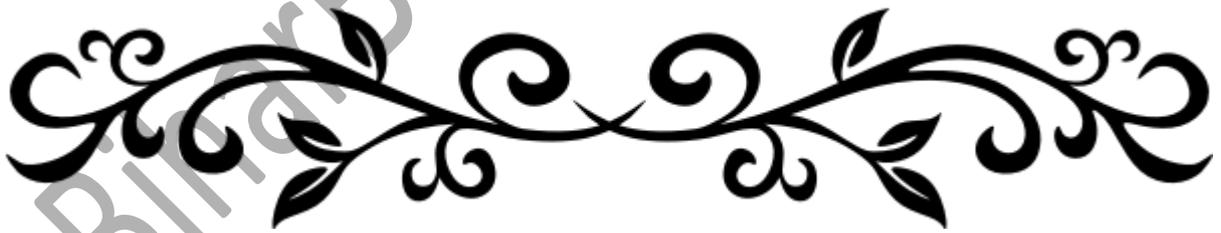
गठन: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) और वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। वे 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। **अधिकार क्षेत्र:**

1. **मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction):** केंद्र और राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (अनुच्छेद 32) के मामले भी इसमें आते हैं।
2. **अपीलीय अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction):** यह देश का अंतिम अपील न्यायालय है। यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील सुनता है।
3. **परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction):** अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है।
4. **रिट अधिकारिता:** यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि रिट जारी कर सकता है। यह 'अभिलेख न्यायालय' भी है, अर्थात् इसके निर्णय नजीर (कानून) माने जाते हैं।

38. भारत की संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए?

भारतीय संविधान ने एक संघीय व्यवस्था स्थापित की है, जिसे अक्सर 'अर्ध-संघात्मक' (Quasi-federal) कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. **द्वैध शासन प्रणाली:** इसमें दो स्तर की सरकारें होती हैं—एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें। दोनों की अपनी-अपनी शक्तियाँ और कार्यक्षेत्र हैं।
2. **शक्तियों का विभाजन:** संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन सूचियों (संघ, राज्य और समवर्ती) के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है।
3. **लिखित और कठोर संविधान:** भारत का संविधान लिखित है और सर्वोच्च है। केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधानों को संशोधित करना कठिन है, जिससे राज्यों के अधिकारों की रक्षा होती है।
4. **स्वतंत्र न्यायपालिका:** एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है जो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है और संविधान की व्याख्या करता है।
5. **द्विसदनीय व्यवस्था:** संसद में दो सदन हैं—लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और संघीय ढांचे को बनाए रखती है। इन विशेषताओं के बावजूद, सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान भारतीय संघ को एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं।



Provided By – BiharBoardBooks.Com

Join Our Telegram Channel - [@BiharBoardBooks](https://t.me/BiharBoardBooks)